मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

थानो में लगाये जायें एटीएम 3
किसान, राजनीति और दुर्गति 4
लड़की कहां जाये अब 5
मोदी से बड़ा झूठा न हुआ 8

वर्ष 31 अंक -41 फ़रीदाबाद 7-13 अक्टूबर 2018 फोन : - 9999595632 2.50 ₹

'ईमानदार' खट्टर की पुलिस द्वारा दहशत से वसूली का एक नमूना

ग्राउंड जीरो से सतीश कुमार की रिपोर्ट

मेरा एक जानकार बिल्डर सेक्टर 21 सी, फ़रीदाबाद में रहता है। बहुत दिन से मिला नहीं था तो जनवरी 2018 के मध्य में मैं उससे मिलने चला गया। वह बिस्तर पर पड़ा था। एक टांग टूटी पड़ी थी। हड्डी के अलावा लिगामेंट्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। पूछने पर उसने कार दुर्घटना की कहानी सुना दी। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, लिहाजा मैं शक के आधार पर हकीकत कुरेदने का प्रयास करता रहा। सात महीने बाद, अगस्त के अंत तक जाकर सच्चाई सामने आ पाई। इसे हर तरह से तसदीक करने के बाद दे रहा हूँ।

वाकया मंगलवार 21 नवम्बर 201। की रात का है। उस जमाने में पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर मोदी सरकार में मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की खडाऊं राज किया करती थी। गुर्जर के इशारे पर पुलिसवालों को तैनाती मिलती ।

बिल्डर मंगलवार को मंदिर जाना नहीं छोड़ता था। उस दिन काफी देर हो जाने के बावजूद रात करीब 11 बजे वह मंदिर की ओर जा रहा था कि एशियन अस्पताल के निकट एक कार उसके बगल में आ लगी और जोर जोर से चिल्ला कर उसे रुकने का इशारा करने लगे। बिल्डर ने रफ्तार बढ़ा कर उनसे भागना चाहा तो उन्होंने भी रफ्तार बढ़ा कर बढ़कल रेलवे फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी आगे लगा दी। जब तक वे लोग अपनी गाड़ी से उतरकर बिल्डर तक पहुँचते, उसने बैक गियर लगा कर अपनी गाड़ी पीछे को भगा ली, डिवाइडर से कुदाकर वापस मोड़ ली और घर की तरफ भागा। उसे लगा था कि कोई फिरौतीबाज उसका अपहरण करना चाहते हैं।

कुछ देर बाद वही गाड़ी फिर उसके पीछे आ लगी। इस भागमभाग में बिल्डर की गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई तो कार सवार लोगों ने उसे दबोच लिया। पहले तो उसे उसकी कार सहित ले जाने की कोशिश की लेकिन जब दुर्घटनाग्रस्त कार चली ही नहीं तो उसको उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लिया। इस दौरान उन हट्टे कट्टे युवकों ने जब बिल्डर को उसकी कार से निकालना चाहा तो उसने स्टीयरिंग व्हील को कस कर पकड़ लिया व पैर नीचे ब्रेक आदि में फंसा लिए। युवकों ने उसके हाथों-पैरों पर घूसों-मुक्कों से इतने वार किये कि उसकी एक टांग बिल्कुल कंडम हो गई। उसके बाद युवकों ने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लिया और आँखों पर काली पट्टी बाँध दी।

बिल्डर के बार बार पूछने पर भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सब कुछ बताएँगे, ठिकाने पर चलकर। चलते वक्त ड्राइवर को कहा गया कि बाईपास की ओर ले

लो। बाईपास से गाड़ी दाहिनी ओर मुड़ी। कुल 10-12 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी सुनसान सी जगह बनी एक छोटी सी इमारत के पास रुकी। बिल्डर को उतारकर एक कोठरी में ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया गया। पट्टी खोल दी गई। एक बल्ब की रोशनी थी। कुछ देर में अधिकारीनुमा एक युवक सामने आया और बोला कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम पुलिस हिरासत में ही हो और उसे पानी भी पिलाया।

उस अफसर ने तीन सूदखोर फाइनेंसरों के नाम लिए जिनसे बिल्डर का लेना-देना था। बिल्डर ने स्वीकार किया कि बिल्कुल लेना-देना है। उसने यह भी बताया कि वह कितना ब्याज दे चुका है और उसका कितना माल (फ्लैट्स आदि) उन फाइनेंसरों के कब्जे में है। युवा अधिकारी ने कहा कि उसे तो सीपी साहब का आदेश है कि फाइनेंसरों का हिसाब चुकता कराना है। इसी वार्तालाप के दौरान उक्त फाइनेंसरों में से दो वहीं मौके पर आ गए। वे अपने साथ कुछ दस्तावेज तैयार कर के लाये थे। अधिकारी के दबाव में दहशतजदा बिल्डर, जहाँ जहाँ वे कहते गए अपने हस्ताक्षर करता चला गया।

काम पूरा होने के बाद बिल्डर को उसके घर पहुँचाने से पहले कढ़ी हिदायत दी गई कि यदि उसने कहीं भी मुंह खोला तो समझ ले क्या हाल होगा, पुलिस कुछ भी कर सकती है। पहले से ही दहशतजदा बिल्डर के लिए यह धमकी बहुत थी। परिणामस्वरूप वह आज तक इस कदर डरा हुआ है कि किसी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।

मैने उसे निर्भय होकर सामने आने के लिए बहुत प्रेरित किया। उसे समझाया कि अब सीपी बदल चुका है, तुम्हारी सुनवाई होगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। इस तरह डर कर जीने से तो मरना बेहतर है। परंतु वह नहीं माना। लिहाजा उसका किस्सा वहीं का वहीं रुका पड़ा है।

यहाँ सवाल एक नागरिक विशेष के दहशतजदा हो कर चुप हो जाने भर का नहीं है। यह शासन, प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था के मुंह पर लगी कालिख का एक उदहारण है। नागरिकों के टैक्स पर पलने वाली जिस पुलिस का दायित्व नागरिकों के जान माल की हिफाजत करना है, वही जब गुंडे बदमाशों की तरह नागरिकों का अपहरण करके उनके हाथ पाँव तोड़ कर सूदखोरों की वसूली करने लगेगी तो कोई कैसे पुलिसवालों और शासकों पर भरोसा करेगा ?

यह भी सत्य है कि चंद प्रतिशत इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाले पूरी फोर्स को बदनाम कर छोड़ते हैं। इस तथ्य की पुष्टि भी इसी कहानी में आगे जाकर तब हुई जब एक अन्य ईमानदार पुलिसकर्मी ने उपरोक्त युवा अधिकारी को इस तरह के गुनाह के प्रति सचेत करते हुए रोका, वरना वह बिल्डर को अभी और भी रगड़ना चाहता था।

जनता में अपनी थोड़ी-मोड़ी विश्वसनीयता एवं शेष छवि को बनाये रखने के लिए पुलिस के लिए यह जरूरी है कि ऐसी काली भेड़ों को चुन चुन कर अपनी कतारों से बाहर करे वरना ऐसे लोग ऐसे ही खराब करतेरहेंगे।

पुलिस की योगी छाप गुंडई का नमूना है विवेक तिवारी हत्याकांड

विकास नारायण राय की विशेष रिपोर्ट

अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिगड़ी हुयी कानून व्यवस्था की स्थिति लाचार पवित्र गाय वाली रही है। हाल के मुख्यमंत्रियों में मायावती ने इसे दुहा, अखिलेश यादव ने इसे चारा खिलाया और अब योगी आदित्यनाथ इसे बचाने में 'विधर्मियों' को मिटाने के संकल्प के साथ जुटे हैं। यानी जिसकी जैसी राजनीति उसकी वैसी ही कानून व्यवस्था के नाम पर रणनीति!

इस क्रम में, लखनऊ के विवेक तिवारी प्रकरण ने रोजमर्रा के दो सम्बंधित मुद्दों को और ज्वलंत करने का काम अंजाम दिया है- एक मुद्दा है, पुलिस की औपनिवेशिक जड़ों का और दूसरा, सत्ता राजनीति के जातिवादी मंचन का।

न ये मुद्दे नये हैं न समाज के लिए इनका घातक होना। लेकिन योगी के राज में इनमें नये मारक आयाम जुड़ गये

हैं। सत्ता के जातिवादी प्रोफाइल का पुलिस के सामंती चरित्र से अघोषित घालमेल तमाम सरकारों में कमोबेश दिखता रहा है; योगी शासन में यह घालमेल सामान्यतः सरकारी नीति के झीने परदे से संचालित किया जा रहा था जिसे विवेक तिवारी हत्याकांड की 'विशिष्टता' ने अब ऐन खुले में नंगा कर दिया।

प्रदेश में सत्ता सम्हालते ही घोषित हो गया था कि योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार के प्रश्न को, एकमात्र पुलिस की सामंती दबंगई से जोड़ने का रास्ता चुना है- एनकाउंटर प्रणाली को, वह भी पिछड़ो के एनकाउंटर को, इसकी स्वाभाविक प्रशाखा कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश, अस्सी के दशक में, वीपी सिंह के मुख्यमंत्रित्व में भी पुलिस एनकाउंटर के खुले खेल का एक सीमित दौर देख चुका है और उसकी व्यर्थता को भी।

ताज्जुब नहीं कि योगी की शातिर राजनीतिक बनावट में किसी असफलता से सबक लेने की जरूरत नहीं हो। भाजपा का मुसलमानों, यादवों और चमारों का राजनीतिक बहिष्कार, सहज ही योगी के 'ऑपरेशन क्लीन' और 'ठोक दो' का भी चेहरा बनता गया है। ऐसे में राजनीतिक विरोधी, मीडिया, नागरिक संगठन, मानवाधिकार आयोग और न्यायपालिका भी योगी सरकार के एनकाउंटर सैलाब के सामने विवश लग रहे थे कि अचानक विनीत तिवारी हत्याकांड का भस्मासुर उसके सामने आन खड़ा हुआ।

भस्मासुर को कैसे छलावे से रोकते हैं, इस पौराणिक पहेली को हल करना एक महंत मुख्यमंत्री और सवर्णवादी भाजपा से बेहतर कौन जानेगा। लिहाजा, पीड़ित परिवार को अप्रत्याशित रूप से भारी मुआवजा और उनकी जातीय-वर्गीय घेरेबंदी की कवायद देखने को मिली! डीजीपी का हत्या-पीड़ित परिवार को संबोधित ताबड़तोड़ माफीनामा भी!

दुर्भाग्य से राज्य शासन और पुलिस प्रशासन ने, स्वयं उनके ही मानदंडों पर भी उन्हें शर्मसार करने वाले इस प्रकरण से कुछ नहीं सीखा है। आजमगढ़ से अलीगढ़ तक अपराध की रोकथाम के नाम पर करीब सौ हत्याएं, योगी के

शेष पेज दो पर